Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था

(मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

भाग–2

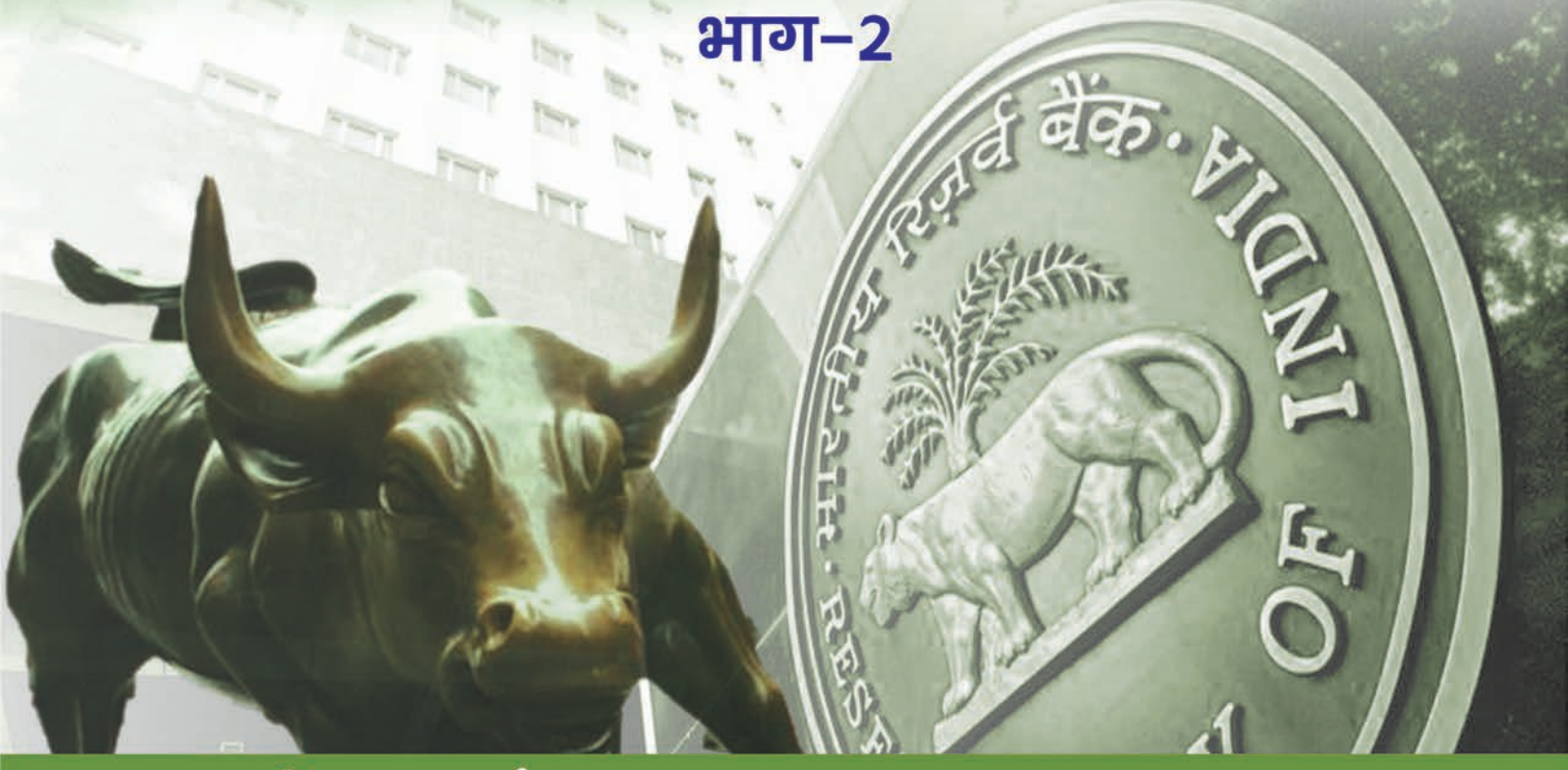

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: MPPM13

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था

(मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

भाग–2

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

MPPCS DLP विषय सूची (Contents)

9. राजकोषीय नीति एवं बजट व्यवस्था **5–53**

9.1 बजट व्यवस्था 5

9.2 केन्द्रीय बजट 2018-19 18

9.3 भारत में कराधान 25

9.4 वस्तु एवं सेवा कर 29

9.5 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें 48

10. विदेशी व्यापार **54-72**

10.1 विदेशी व्यापार : सामान्य परिचय 54

10.2 विदेशी व्यापार की संरचना 56

10.3 निर्यात संवर्द्धन 59

10.4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते 63

10.5 विदेश व्यापार नीति, 2015–20 68

11. भुगतान संतुलन **73–93**

11.1 भुगतान संतुलन : अर्थ एवं अवधारणा 73

11.2 भुगतान शेष प्रबंधन 79

11.3 रुपए की परिवर्तनीयता 82

11.4 विदेशी निवेश 85

11.5 विदेशी पूंजी का नियमन 89

12. अंतर्राष्ट्रीय संगठन **94–127**

12.1 संयुक्त राष्ट्र संघ 94

12.2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन 96

12.3 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंकटाड, यूनेस्को, यू.एन.डी.पी., जी–20 103

12.4 सार्क, ब्रिक्स, बिम्सटेक, आसियान, एपेक, शंघाई सहयोग संगठन 110

12.5 न्यू डेवलपमेंट बैंक (ब्रिक्स बैंक), एशियाई विकास बैंक 116

12.6 गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नाटो 118

13. नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे **128–162**

13.1 अवसंरचना 128

13.2 निम्न आय वर्गीय समूह के लिए आवास 129

13.3 नगरीय क्षेत्र के मुद्दे : शहरीकरण से उपजी समस्याएँ 131

13.4 शहरी अवसंरचना : आवास, स्वच्छता और अवसंरचना विकास योजनाएँ 133

13.5 ग्रामीण अवसंरचना : आवास, स्वच्छता और अवसंरचना विकास योजनाएँ 144

13.6 ग्रामीण साख 155

14. सहकारिता आंदोलन **163–171**

14.1 सहकारिता : सामान्य परिचय 163

14.2 भारत में सहकारिता आंदोलन 164

14.3 मध्य प्रदेश में सहकारिता आंदोलन 166

15. योजनाएँ **172–196**

15.1 केंद्र सरकार की योजनाएँ 172

15.2 मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएँ 184

15.3 विविध 186

16. आर्थिक अवधारणाएँ तथा शब्दावलियाँ **197–200**

अध्याय
9

राजकोषीय नीति एवं बजट व्यवस्था (Fiscal Policy and Budget System)

अर्थशास्त्री कींस की पुस्तक **द जनरल थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट एंड मनी** में प्रतिपादित विचारों में एक विचार यह भी है कि सरकार को राजकोषीय नीति का प्रयोग निर्गत और रोज़गार को स्थिर करने के लिये किया जाना चाहिये। कींस के अनुसार सरकार को करों तथा व्यय में परिवर्तनों के माध्यम से राजकोषीय नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास करना चाहिये।

राजकोषीय नीति : अर्थ *(Fiscal policy : Meaning)*

राजकोषीय नीति से तात्पर्य कर, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण का प्रबंध किन्हीं सुनिश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने से है।

भारत की राजकोषीय नीति *(Fiscal policy of India)*

भारत की राजकोषीय नीति के वृहद् उद्देश्यों के अंतर्गत संतुलित एवं तीव्र विकास, कल्याणकारी राज्य की स्थापना और समाजवादी ढंग के समाज की रचना करना इत्यादि शामिल हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित राजकोषीय नीतियाँ अपनाई गईं–

1. ग्रामीण आधार संरचना पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि करना ताकि कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाया जा सके।
2. पूर्ण रोज़गार की स्थिति प्राप्त करने के लिये प्रयास करना।
3. सार्वजनिक क्षेत्र की घाटे में चल रही इकाइयों में विनिवेश की प्रक्रिया जारी रखना।
4. राजकोषीय घाटे को निकट भविष्य में यथासंभव शून्य करना।
5. राजकोषीय घाटे को संघ और राज्य के लिये क्रमशः 3% और 2% से कम करना।
6. महत्त्वहीन वस्तुओं (Non Merit Goods) पर दी जा रही सब्सिडी को कम करना एवं वैसी छिपी हुई सब्सिडी भी घटाना जो समर्थ लोगों को अधिक लाभ पहुँचा रही है।
7. भुगतान संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिये प्रयास करना।

9.1 बजट व्यवस्था *(Budget System)*

सरकार राजकोषीय नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये बजट व्यवस्था के अंतर्गत अपने आय-व्यय को समायोजित करती है। बजट एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। भारतीय संविधान में 'बजट' शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। संविधान में बजट के लिये **वार्षिक वित्तीय विवरण** अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 (1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिये अनुमानित प्राप्तियाँ एवं व्यय का विवरण रखवाएगा। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को केंद्र सरकार का बजट कहा गया है।

याद रखें (Remember)

- स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर, 1947 को प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षण्मुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया।
- जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव हासिल हुआ।

बजट में लगातार तीन वर्षों के व्ययों तथा प्राप्तियों का विवरण दिया रहता है।

1. आने वाले वर्ष के लिये बजट अनुमान। इसका अर्थ है कि यदि वर्ष 2017–18 में बजट पेश किया जा रहा है तो वर्ष 2018–19 का अनुमान।

भारत के वित्त आयोग (Finance Commissions of India)				
क्रमांक	गठन का वर्ष	अध्यक्ष का नाम	क्रियान्वयन वर्ष	रिपोर्ट देने का वर्ष/तिथि
पहला	1951	के.सी. नियोगी	1952–57	1952
दूसरा	1956	के. संथानम	1957–62	1956 व 1957
तीसरा	1960	ए.के. चंद्रा	1962–66	1961
चौथा	1964	डॉ. पी.वी. राजामन्नार	1966–69	1965
पाँचवा	1968	महावीर त्यागी	1969–74	1968 व 1969
छठा	1972	ब्रह्मानंद रेड्डी	1974–79	1973
सातवाँ	1977	पी.एम. शेलेट	1979–84	1978
आठवाँ	1983	वाई.बी. चव्हाण	1984–89	1983 व 1984
नवाँ	1987	एन.के.पी. साल्वे	1989–95	1988 व 1989
दसवाँ	1992	के.सी. पंत	1995–2000	26 नवंबर, 1994
ग्यारहवाँ	1998	ए.एम. खुसरो	2000–05	15 जनवरी, 2000; 7 जुलाई, 2000 एवं 30 अगस्त, 2000
बारहवाँ	2002	सी. रंगराजन	2005–10	30 नवंबर, 2004
तेरहवाँ	2007	विजय एन. केलकर	2010–15	30 दिसंबर, 2009
चौदहवाँ	2013	वाई.वी. रेड्डी	2015–20	15 दिसंबर, 2014

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- भारत में बजट का राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है।
- सरकार के खज़ाने में कर जमा करने का दायित्व जिसके ऊपर है उसे करापात कहते हैं।
- राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय करता है जबकि मौद्रिक नीति आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित की जाती है।
- बजट के हिसाब-किताब की जाँच भारतीय संसद की सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा की जाती है।
- मूल्य संवर्द्धन कर इनवॉयस विधि के प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- केंद्र सरकार के संपूर्ण व्यय प्रारूप की समीक्षा हेतु व्यय सुधार आयोग का गठन 28 फरवरी, 2000 को किया गया।
- भारत की संचित निधि से होने वाला व्यय और भारित व्ययों के लिये संसदीय मंज़ूरी विनियोग विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- राजकोषीय घाटे की गणना में केवल 91 दिन की परिपक्वता वाली सरकारी हुंडियों (Treasury Bill) को ही सम्मिलित किया जाता है।
- भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर देश में ही उगाहे गए ऋण आंतरिक ऋण कहलाते हैं।
- कर का अंतत: मौद्रिक बोझ किसके ऊपर है इसे हम कराघात कहते हैं।
- जी.एस.टी. लागू करने के लिये 122वें संशोधन विधेयक, 2014 द्वारा संविधान में 101वाँ संशोधन 2016 किया गया तथा संविधान में नए अनुच्छेद-246(ए), 269(ए) और 279(ए) की व्यवस्था की गई है।
- ऐसी वस्तुएँ तथा सेवाएँ जिनमें एक व्यक्ति के उपभोग में कमी किये बिना दूसरे व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि की जा सके। इनके उपभोग से कोई व्यक्ति इसलिये वंचित नहीं रह सकता क्योंकि वह उनकी कीमत चुकता नहीं कर सकता ऐसी वस्तुएँ शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएँ कहलाती हैं।

- शुद्ध निजी वस्तुएँ ऐसी वस्तुएँ एवं सेवाएँ हैं जिनमें एक व्यक्ति के उपभोग में कमी करने पर दूसरे व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि हो क्योंकि वह व्यक्ति उनकी कीमत चुकता कर सकता है।
- प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को वर्ष 2011–12 के केंद्रीय बजट से शुरू किया गया था।
- वर्ष 2012–13 के बजट में प्रभावी राजस्व घाटे को एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया।
- सक्षम परियोजना से वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
- इसके अलावा व्यापार में सुगमता के लिये भारतीय सीमा शुल्क एकल खिड़की इंटरफेस (स्विफ्ट) का विस्तार और डिजिटल इंडिया के तहत अन्य करदाता अनुकूल पहलों और कारोबार सुगमता में भी मदद मिलेगी।
- जी.एस.टी. के लागू होने से सी.बी.ई.सी. के तहत विभिन्न अप्रत्यक्ष कानूनों में सभी करदाताओं-आयातकों-निर्यातकों-डीलरों की संख्या बढ़कर 65 लाख हो जाएगी जो फिलहाल 36 लाख है।
- पंजीकरण, भुगतान, सी.बी.ई.सी. को भेजे जाने वाले रिटर्न डेओ की प्रोसेसिंग के आई.टी. ढाँचे का वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) से एकीकरण ज़रूरी है। इसके अलावा 'सक्षम' अन्य मॉड्यूल, मसलन-ऑडिट, अपील तथा जाँच में भी प्रमुख भूमिका निभाएगा।
- 14वें वित्त आयोग ने प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को समाप्त करने की संस्तुति की है क्योंकि यह अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार से मेल नहीं खाती।
- प्राथमिक घाटे का सर्वप्रथम वर्ष 1994–95 के बजट में प्रयोग करने वाले व्यक्ति वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह थे।
- राजस्व तथा प्राथमिक घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटे का आकार सबसे बड़ा है। सरकारी बजट घाटे की स्पष्ट तस्वीर राजकोषीय घाटा प्रस्तुत करता है।
- बिक्री कर वह कर है जो वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर लगता है, यह अधिवासी निकाय को चुकाया जाता है। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे केंद्रशासित राज्यों पर यह कर लागू नहीं है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. 'वस्तु एवं सेवा कर' एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे– **M.P.P.C.S. (Pre) 2017**
   (a) विजय केलकर (b) मोंटेक सिंह अहलूवालिया
   (c) अरुण जेटली (d) नरसिम्हा
2. भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है– **M.P.P.C.S. (Pre) 2005**
   (a) राजस्व घाटा (b) आय-व्यय घाटा
   (c) राजकोषीय घाटा (d) प्राथमिक घाटा
3. सेवा कर की वर्तमान दर भारत में कितने प्रतिशत है? **M.P.P.C.S. (Pre) 2005**
   (a) 14% (b) 12%
   (c) 10% (d) 8%
   नोट: यह दर जीएसटी लागू होने से पूर्व की है।
4. संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया? **M.P.P.C.S. (Pre) 2005**
   (a) 1991 (b) 1976
   (c) 1957 (d) 1948
5. बारहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? **M.P.P.C.S. (Pre) 2005**
   (a) अमर्त्य सेन
   (b) सी. रंगराजन
   (c) वी.वी. रेड्डी
   (d) विमल जालान
   नोट: वर्तमान में वाई.वी. रेड्डी हैं।
6. किस राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र में बिक्री कर लागू नहीं है? **M.P.P.C.S. (Pre) 2005**
   (a) अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप
   (b) पांडिचेरी
   (c) गोवा, अरुणाचल प्रदेश
   (d) सभी राज्य एवं केंद्रशासित क्षेत्रों में बिक्री कर लागू है।
7. उत्पाद शुल्क क्या है? **M.P.P.C.S. (Pre) 2004**
   (a) प्रत्यक्ष कर
   (b) अप्रत्यक्ष कर
   (c) एक प्रकार का उपभोग कर
   (d) एक प्रकार का विक्रय कर

8. भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है?
(a) वित्त मंत्रालय (b) वित्त आयोग
(c) योजना आयोग (d) आर.बी.आई.

9. भारत में बजट का राजस्व तैयार किया जाता है–
(a) प्रत्यक्ष कर के केंद्रीय बोर्ड द्वारा
(b) मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा
(c) संबंधित आयोगों द्वारा
(d) वित्त मंत्रालय द्वारा

10. भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई?
(a) वी.पी. सिंह (b) पी. चिदंबरम
(c) डॉ. मनमोहन सिंह (d) यशवंत सिंह

11. सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है–
(a) वित्त मंत्रालय (b) योजना आयोग
(c) भारतीय रिज़र्व बैंक (d) वित्त आयोग

12. निम्नलिखित में से कौन-सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता?
(a) सेवा कर (b) शिक्षा कर
(c) सीमा कर (d) मार्ग कर

13. तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि है–
(a) वर्ष 2009–14 (b) वर्ष 2010–15
(c) वर्ष 2007–12 (d) वर्ष 2005–10

14. केलकर टास्क फोर्स सिफारिशों का संबंध है–
(a) व्यापार से (b) बैंकिंग से
(c) विदेशी निवेश से (d) करों से

15. वर्ष 2017–18 के अनुसार केंद्र एवं राज्यों का राजस्व घाटा लगभग होना चाहिये-
(a) 0% (b) 1.9%
(c) 2% (d) 3%

16. भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे कम योगदान है?
(a) राजस्व घाटा (b) आय-व्यय घाटा
(c) राजकोषीय घाटा (d) प्राथमिक घाटा

17. बजट एक लेख-पत्र है-
(a) सरकार की मौद्रिक नीति का
(b) सरकार की वाणिज्य नीति का
(c) सरकार की राजकोषीय नीति का
(d) सरकार की मुद्रा बचत नीति का

18. भारत में केंद्र सरकार की कर आय में मुख्यत: दो सबसे बड़े स्रोत हैं–
(a) केंद्रीय उत्पाद कर और निगम कर
(b) तट कर और आयकर
(c) तट कर और निगम कर
(d) निगम कर एवं आयकर

19. यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा–
(a) सकल प्राथमिक घाटा (b) बजटीय घाटा
(c) मौद्रीकृत घाटा (d) राजस्व घाटा

20. राजकोषीय घाटा है–
(a) कुल व्यय – कुल प्राप्तियाँ
(b) राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ
(c) पूंजीगत व्यय – पूंजीगत प्राप्तियाँ – बाज़ार ऋण
(d) बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाज़ार ऋण तथा दायित्व

21. यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह किसके बराबर होगा?
(a) बजट घाटे के
(b) राजकोषीय घाटे के
(c) घाटे की वित्त व्यवस्था के
(d) आगामी घाटे के

22. निम्नलिखित में से कौन-सा आंतरिक ऋण का घटक है?
(1) बाज़ार ऋणदान (2) ट्रेज़री बिल्स
(3) भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूति
कूट:
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

23. निम्नलिखित में से कौन-सा एक राजकोषीय नीति का भाग है?
(a) उत्पादन नीति (b) कर नीति
(c) विदेश नीति (d) ब्याज दर नीति

24. भारत में मूल्य संवर्द्धित कर निम्नलिखित से किसका स्थान लेगा?
(a) विक्रय और क्रय दर (b) प्रवेश कर
(c) पण्यावर्त कर (d) उपर्युक्त सभी

25. मूल्य वर्द्धित टैक्स (VAT) लगाया जाता है–
(a) प्रत्यक्ष रूप में उपभोक्ता पर
(b) उत्पादन के अंतिम स्तर पर
(c) उत्पादन के प्रथम स्तर पर
(d) उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर

26. निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है?
(a) आयकर (b) सार्वजनिक ऋण
(c) वैट (d) अर्थसहायिकी परिदान

27. एडहॉक ट्रेजरी बिल का स्थान निम्नलिखित में से किसने लिया है?
(a) अर्थोपाय अग्रिम (b) वाणिज्यिक पत्र
(c) जमा प्रमाण पत्र (d) विनिमय विपत्र

28. एफ.आर.बी.एम. भारत में कब पारित किया गया?
(a) 2007 (b) 2005
(c) 2002 (d) 2003

उत्तरमाला

1. (a)	2. (c)	3. (b)	4. (c)	5. (b)	6. (a)	7. (b)	8. (a)	9. (d)	10. (a)
11. (a)	12. (d)	13. (b)	14. (d)	15. (b)	16. (d)	17. (c)	18. (d)	19. (a)	20. (d)
21. (b)	22. (d)	23. (b)	24. (d)	25. (d)	26. (d)	27. (a)	28. (d)		

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिये)

(a) राजस्व घाटा किस प्रकार निश्चित होता है? **M.P.P.C.S. (Mains) 2014**

(b) मूल्य वृद्धि कर किस प्रकार लगाया जाता है? **M.P.P.C.S. (Mains) 2014**

(c) केंद्र सरकार अपने बजट में सामाजिक क्षेत्र के किन मदों पर सामान्यतया व्यय करती है? **M.P.P.C.S. (Mains) 2014**

(d) करारोपण में प्रतिगामी, आनुपातिक तथा प्रगतिशील प्रणाली का क्या अर्थ है?

(e) शून्याधार बजट की परिभाषा दीजिये।

(f) वित्त आयोग क्या होता है?

(g) जेंडर बेस बजट को समझाइये।

(h) मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली क्या होती है?

(i) लैफर वक्र क्या होता है?

(j) सार्वजनिक वस्तुएँ निजी वस्तुओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं?

(k) क्या भारत को बाह्य ऋण की आवश्यकता है? अपने विचार प्रकट करें।

(l) राजस्व घाटा तथा प्राथमिक घाटा को परिभाषित करें।

(m) जी.एस.टी. प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें।

(n) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की उदाहरण सहित व्याख्या करें।

(o) वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2003 को प्रारंभ करने के क्या कारण थे?

लघु व दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100 या 300 शब्दों में दीजिये)

1. एक देश के आर्थिक विकास में जन वित्त की भूमिका क्या है? **(100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2015**
2. 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात् भारत के सार्वजनिक ऋण की स्थिति बताइये। **(100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2014**
3. भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के प्रमुख घटक क्या-क्या हैं? इस ऋण की हाल ही में बढ़ती प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिये।
4. 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत दिये गए बिंदुओं पर प्रकाश डालें।
5. भारत जैसे विकासशील देश में आपके विचार में जी.एस.टी. प्रणाली कितनी सार्थक होगी? अपने तर्कों को स्पष्ट कीजिये।
6. भारत की आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा निधि क्या है? इनका संचालन कैसे किया जाता है?
7. भारत में सार्वजनिक व्यय को संसद जिन विधियों से नियंत्रित करती है, उनकी विवेचना कीजिये।
8. भारत में नई आर्थिक नीति के आने के बाद किये गए कर सुधारों को अपने शब्दों में बतलाएँ।
9. क्या राजकोषीय घाटे को कम करने से मुद्रास्फीति कम हो जाएगी? अपने तर्क दें।
10. क्या आयकर आर्थिक विषमता को कम करता है? अपने विचार प्रकट कीजिये।
11. भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक ऋण की भूमिका क्या है?

अध्याय
10

विदेशी व्यापार (Foreign Trade)

वैश्वीकरण के दौर में विश्व व्यापार एक अपरिहार्य आवश्यकता है। वैश्विक व्यापार में वृद्धि होने से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निर्भरता भी निरंतर बढ़ रही है। विदेशी व्यापार का अर्थ दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार है। किसी भी देश के विदेशी व्यापार में उसके आयात और निर्यात दोनों घटकों को शामिल किया जाता है। कोई भी देश उत्पादन एवं उपभोग क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होता है इसलिये विदेशी व्यापार अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी व्यापार के बिना देश अपनी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं तक सीमित रह जाएंगे। इसी कमी को दूर करने के लिये विदेशी व्यापार की आवश्यकता का जन्म हुआ है। विदेशी व्यापार को विश्व व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक सहयोग से एक-दूसरे पर निर्भरता तथा एक-दूसरे की भागीदारी एवं सहायता से आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।

10.1 विदेशी व्यापार : सामान्य परिचय *(Foreign Trade : General Introduction)*

"दो राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय-विक्रय को विदेशी व्यापार कहते हैं।" किसी देश के विदेशी व्यापार से उसकी अर्थव्यवस्था की प्रकृति और उसके आकार का पता चलता है। विदेश व्यापार किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्रिया में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण द्वारा उत्पादन साधनों की दक्षता और कार्य कुशलता में वृद्धि कर आर्थिक उन्नयन करता है। खुली अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। विदेशी व्यापार की महत्ता वैश्वीकरण के इस दौर में बहुत अधिक बढ़ गई है। किसी भी देश के लिये विदेशी व्यापार का महत्त्व निम्नलिखित रूप में है-

1. यह विदेशी मुद्रा अर्जन का प्रमुख साधन है।
2. विभिन्न देशों के मध्य पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करता है।
3. आवश्यक वस्तुओं के आयात तथा अधिशेष वस्तुओं के निर्यात से अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित होता है।
4. बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन करता है।
5. मशीनरी, तकनीक एवं पूंजीगत आयात से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक मज़बूती आती है।
6. विदेशी व्यापार किसी भी राष्ट्र की उन्नति का महत्त्वपूर्ण कारक है।

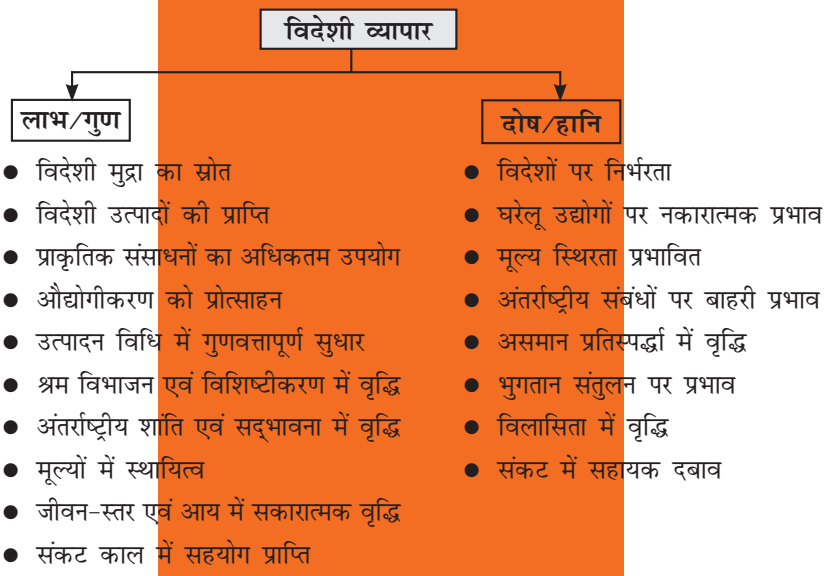

अध्याय
11

भुगतान संतुलन (Balance of Payment)

किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं संवृद्धि में उस राष्ट्र के आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी राष्ट्र की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आंतरिक साधनों एवं क्रियाओं के द्वारा नहीं की जा सकती इसलिये बाह्य या विदेशी व्यापार को अनुकूल रखे जाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। देश की आर्थिक प्रगति के लिये निर्यात बढ़ाने एवं आयात निर्भरता कम करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। निर्यात में वृद्धि भुगतान संतुलन एवं विदेशी विनिमय कोष के लिये भी आवश्यक है। किसी भी देश के विदेशी लेन-देन का पूर्ण विवरण भुगतान संतुलन के माध्यम से ज्ञात होता है। भुगतान संतुलन किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को चालू खाते एवं पूंजीगत खातों के माध्यम से प्रस्तुत करता है।

11.1 भुगतान संतुलन : अर्थ एवं अवधारणा *(Balance of Payment : Meaning and Concepts)*

किसी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि सामान्यत: एक वित्तीय वर्ष में उस देश और शेष विश्व के साथ उसके सभी व्यापार, जिनके मौद्रिक मूल्य की गणना हो सकती है, का क्रमबद्ध विवरण होता है। दूसरे शब्दों में भुगतान संतुलन खाते इस प्रकार के खाते होते हैं जिनमें किसी अर्थव्यवस्था अथवा देश का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक लेन-देन (Monetary Transactions) का लेखांकन दर्ज किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के आर्थिक लेन-देन (दृश्य, अदृश्य या पूंजीगत) का समस्त विवरण उपलब्ध होता है।

कोई देश जब विश्व के अन्य देशों को वस्तु एवं सेवाएँ विक्रय करता है तो उसे निर्यात कहते हैं तथा दूसरे देशों से जिन वस्तु एवं सेवाओं का क्रय करता है उसे हम उसका आयात कहते हैं। आयात-निर्यात के दौरान दृश्य मदों एवं अदृश्य मदों के तहत प्रविष्टि की जाती है। दृश्य मदों के अंतर्गत वस्तुओं के आदान-प्रदान तथा अदृश्य मदों के अंतर्गत सेवाओं (पर्यटन, चिकित्सा, कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर, शिक्षा) के आदान-प्रदान को सम्मिलित किया जाता है। पूंजी खाते के अंतर्गत बैंकिंग जमा, विदेशी ऋण, विदेशी निवेश, आप्रवासियों और एन.आर.आई. जमा आदि को सम्मिलित किया जाता है।

चालू खाता (Current Account)	व्यापार खाता (Trade Account)	1. निर्यात (Export – X) 2. आयात (Import – M) 3. व्यापार शेष (Balance of Trade or X – M)
	अदृश्य खाता (Invisible Account)	4. अदृश्य शेष (Invisible Balance) (क) कारक सेवा व्यापार शेष (Factor service Balance of Trade) (i) निजी अंतरण/प्रेषण (Private Transfer/Remittance) (ii) निवेश आय (Investment Income) (ख) गैर-कारक सेवा व्यापार शेष (Non–Factor Service Balance of Trade)
	वस्तु एवं सेवा खाता (Goods and Service Account)	5. वस्तु एवं सेवा शेष (3 + 4 ख) (Goods and Service Balance)
	चालू खाता (Current Account)	6. चालू शेष (3 + 4 क + 4 ख) (Current Balance)

अध्याय
12

अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Organisation)

'अंतर्राष्ट्रीय संगठन' पद का प्रयोग सर्वप्रथम स्कॉटलैंड के प्रमुख विधिवेत्ता जेम्स लोरिमर ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिनके सदस्य, कार्यक्षेत्र, प्रकृति, भूमिका एवं विस्तार वैश्विक स्तर पर हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आधारशिला अपने हितों की रक्षा के लिये विभिन्न राज्यों के मध्य स्वेच्छापूर्ण तरीके के स्वीकार्य अनुशासन एवं नियंत्रण की आवश्यकता ने रखी। विभिन्न देशों द्वारा अपनी समस्याओं तथा अन्य वैश्विक विवादों पर साझा विचार-विमर्श के माध्यम से सहमति एवं समाधान प्राप्त करने तथा पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निष्पक्ष एवं तटस्थ मंच की स्थापना की आवश्यकता ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म दिया। ये संगठन विभिन्न राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करते हुए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सहयोग एवं स्पर्द्धा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई प्रकार की श्रेणियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्यरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के लिये संयुक्त राष्ट्र संगठन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

इसी संदर्भ में देखें तो, वैश्विक स्तर पर पूंजी एवं तकनीकी के लेन-देन के माध्यम से संतुलित एवं समन्वित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिये मुक्त व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन से आसियान, सार्क, शंघाई सहयोग संगठन, एपेक, यूरोपीय यूनियन आदि जैसे संगठन भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

12.1 संयुक्त राष्ट्र संघ *(United Nations)*

क्या यह एक विचित्र संयोग है कि मानव आचरण में युद्ध एवं शांति, विध्वंस एवं निर्माण के बीज एक साथ निहित दिखाई देते हैं जैसा कि नेपोलियन युद्धों के बाद होली एलायंस, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् राष्ट्र संघ की स्थापना एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसके प्रमाण के रूप में दिखाई देते हैं।

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् राष्ट्र संघ की स्थापना में जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैसी ही भूमिका एक अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट की थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर करने के साथ हुई। दो विश्व युद्धों की विभीषिका एवं राष्ट्र संघ की असफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं सहयोग की आवश्यकता ने संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) में है और इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या 193 है। 24 अक्टूबर को हर वर्ष 'संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस' के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (पुर्तगाल) हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य *(Objectives of United Nations)*

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं-

- अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना।
- समान अधिकार और लोगों को आत्म-निर्णय सिद्धांत के आधार पर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना।
- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय समस्याओं के समाधान के लिये सहयोग करना और मानवाधिकारों एवं बुनियादी स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।
- इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास कर रहे देशों की गतिविधि में समन्वय स्थापित करने के लिये एक केंद्र के रूप में कार्य करना।

अध्याय
13

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे (Issues of Urban and Rural Areas)

"आदर्श समाज गतिशील होना चाहिये, उसमें एक भाग में हो रहे परिवर्तन को दूसरे भाग तक पहुँचाने के भरपूर माध्यम होने चाहिये।"

–डॉ. बी.आर. अंबेडकर

विकास परिवर्तन की एक ऐसी सतत् प्रक्रिया है, जो लोगों को इस योग्य बनाती है कि वे सक्षम एवं सृजनात्मक बन सकें। विकास सकारात्मक परिवर्तन को इंगित करता है। पिछड़ेपन के साथ मानव विकास संभव नहीं है इसलिये विकास योजनाएँ मानव विकास तथा उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिये लक्ष्य करके बनाई जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम की ओर से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें जीवन-स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समानता आदि मानकों को विकास का प्रमुख वाहक माना जाता है। विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास करती है। इस रूप में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार नीति प्रतिपादन किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को आगे बढ़ाने में नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों की महत्त्वपूर्ण एवं समान भूमिका है। चूँकि विकास का प्रमुख वाहक आधारभूत संरचना को माना जाता है इसलिये आधारभूत संरचना या अवसंरचना के विकास पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। अवसंरचना विकास समावेशी विकास, आर्थिक संवृद्धि, निर्धनता कम करने तथा वृहत् विकास लक्ष्यों को पाने के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है।

13.1 अवसंरचना *(Infrastructure)*

किसी भी अर्थव्यवस्था के सुचारु रूप से कार्य करने, विकास करने एवं प्रगति के लिये जिन सुविधाओं, क्रियाओं व सेवाओं की आवश्यकता होती है, उसे अवसंरचना, अधोसंरचना या आधारभूत संरचना कहा जाता है। अवसंरचना आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के मूल तत्त्व को प्रकट करती है तथा सहयोगी व्यवस्था का कार्य करती है, जैसे-सड़क, बिजली, परिवहन, संचार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था, ऊर्जा आदि।

अवसंरचना या आधारभूत संरचना को दो भागों में विभाजित किया जाता है-

(1) *आर्थिक अवसंरचना (Economic Infrastructure)*

इसके अंतर्गत उन सभी तत्त्वों को सम्मिलित किया जाता है जो आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ हैं एवं उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। आर्थिक विकास की बुनियादी आवश्यकता के घटकों को आर्थिक अवसंरचना कहा जाता है। इसमें शक्ति, परिवहन, दूरसंचार आदि को सम्मिलित किया जाता है।

(2) *सामाजिक अवसंरचना (Social Infrastructure)*

इसके अंतर्गत उन सभी तत्त्वों को सम्मिलित किया जाता है जो सामाजिक गतिविधियों के विस्तार एवं विकास में सहायक हैं तथा सहयोगी भूमिका निभाते हैं। ये मानव संसाधन विकास और मानव पूंजी निर्माण में सहायक हैं। समाज को कुशल, निपुण एवं स्वस्थ मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली अवसंरचना को सामाजिक अवसंरचना कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि को शामिल किया जाता है।

अवसंरचना की भूमिका *(Role of infrastructure)*

देश के आर्थिक विकास एवं प्रगति में अवसंरचना की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचनाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं। सामाजिक अवसंरचनात्मक ढाँचे के बिना आर्थिक अवसंरचनात्मक ढाँचे का कोई अर्थ नहीं है तथा आर्थिक अवसंरचनात्मक ढाँचे के बिना सामाजिक अवसंरचनात्मक ढाँचा औचित्यहीन है। इसलिये सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना का संयुक्त विकास आवश्यक है। ये निम्नलिखित भूमिका निभाती हैं-

अध्याय
14

सहकारिता आंदोलन
(Co-operative Movement)

आधुनिक काल में सहकारिता की आवश्यकता एवं महत्त्व बहुत अधिक है। यह शांतिपूर्ण तरीके से तृणमूल स्तर पर सामाजिक परिवर्तन लाने और एक शोषण रहित एवं समानता आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने का प्रमुख साधन है। सहकारिता एक ऐसा स्वेच्छापूर्ण संगठन है जो लोकतंत्र, समानता व आत्म-सहायता के आधार पर निजी हित एवं संपूर्ण समुदाय के हित के लिए कार्य करता है। सहकारिता एक सामाजिक-आर्थिक आंदोलन है जो परस्पर सामंजस्य पर आधारित प्रयास में विश्वास करता है।

आर्थिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने में सहकारिता आंदोलन का विशेष महत्त्व रहा है। सहकारी समितियों का समाज में इतना अधिक महत्त्व इसलिए है क्योंकि यह संगठन शोषण रहित सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करने में सहायक है। सहकारी समितियों का उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अधिकतम सुविधाएँ व्यापक जनहित में उपलब्ध कराना होता है।

14.1 सहकारिता : सामान्य परिचय *(Co-operative : General Introduction)*

सहकारिता का अर्थ *(Meaning of Co-operative)*

एच. डैलबर्ट– "सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मानवतापूर्ण ढंग से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए संगठित होते हैं।" सहकारिता शब्द 'सह+कारिता' के योग की निर्मिति है जहाँ 'सह' का अर्थ है- 'मिल-जुलकर या साथ-साथ तथा 'कारिता' का अर्थ है- कार्य करना। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें समानता को आधार बनाकर पारस्परिक हितों को ध्यान में रखकर एक साथ मिल-जुलकर काम किया जाता है। सहकारिता 'एक सबके लिये और सब एक के लिये' की अवधारणा पर अवलंबित है। सहकारिता आत्म-सहायता, स्व-उत्तरदायित्व, लोकतंत्र, समानता, समता और एकजुटता के मूल्यों पर आधारित है।

सहकारी संगठनों की विशेषताएँ *(Characteristics of co-operative organizations)*

सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें मनुष्य समानता के आधार पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सहयोग करते हैं। इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

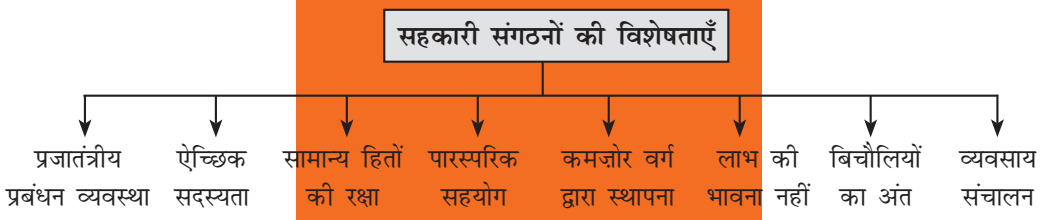

- **प्रजातंत्रीय प्रबंधन व्यवस्था :** इसमें सभी सदस्यों द्वारा चुनी हुई समिति प्रबंधन कार्य करती है। 'एक व्यक्ति एक मत' का सिद्धांत लागू होता है चाहे व्यक्ति के पास कितना ही अंश क्यों न हो।
- **ऐच्छिक सदस्यता :** इसमें व्यक्ति स्वेच्छा से शामिल होते हैं। इसके सदस्य बनने हेतु समिति में अंशदान करना होता है। इसके सदस्य जब चाहें इससे अलग हो सकते हैं।

अध्याय
15

योजनाएँ (Schemes)

एक कल्याणकारी राष्ट्र में गरीबों एवं वंचित वर्गों के गरिमापूर्ण जीवन के लिये सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जाती हैं। योजनाओं के माध्यम से सरकार आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इसी संदर्भ में केंद्र एवं मध्य प्रदेश सरकार की कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाओं का वर्णन यहाँ किया जा रहा है।

15.1 केंद्र सरकार की योजनाएँ *(Central Government's Schemes)*

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना *(Pradhanmantri Fasal Bima Yojana)*

- इस योजना को 13 जनवरी, 2016 को मंज़ूरी प्रदान की गई।
- यह योजना वर्ष 2016 के खरीफ सत्र से लागू है।
- प्राकृतिक आपदा (चक्रवात, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, तूफान इत्यादि), कीटों एवं बीमारियों का प्रकोप व मौसमी गतिविधियों के कारण प्रभावित फसल, बुआई व कटाई के पश्चात् नुकसान को इस श्रेणी में रखा गया है।
- किसानों को कृषि क्षेत्र में नवाचार एवं आधुनिक पद्धति को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है।
- किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिये केवल 2% तथा रबी फसल के लिये 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये प्रीमियम 5% निर्धारित किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा 2018–19 के बजट में प्रस्तुत योजना के लिये 13000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

कृषि डाक प्रसार सेवा *(Krishi Dak Prasar Seva)*

- यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों तक बीज पहुँचाने के लिये भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित सेवा है, जिसके तहत चिह्नित किसानों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा उन्नत बीज पहुँचाए जा रहे हैं।
- खेती की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य है चिह्नित गाँवों के किसानों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा उन्नत बीजों को डाक के माध्यम से पहुँचाना।
- वर्तमान में यह योजना देश के 14 राज्यों के 100 ज़िलों में शुरू की गई है। इसे कृषि विज्ञान केंद्रों एवं डाकघरों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

किसान कॉल सेंटर *(Kisan Call Center)*

- कृषि में आई.सी.टी. (Information and communication technology) को ध्यान में रखकर कृषि मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी, 2004 को किसान कॉल सेंटर योजना को प्रारंभ किया गया था। ये कॉल सेंटर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के 14 विभिन्न स्थानों में कार्यरत हैं। इसके लिये देशव्यापी 11 अंकों वाली एक टोल फ्री नंबर-18001801551 जारी किया गया।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान स्थानीय भाषा में किसानों को मोबाइल फोन के माध्यम से उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन *(Rashtriya Gokul Mission)*

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 28 जुलाई, 2014 को देशी गायों के संरक्षण तथा उनकी नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई। यह परियोजना 'राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम' का हिस्सा है। इस मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

अध्याय
16

आर्थिक अवधारणाएँ तथा शब्दावलियाँ (Economic Concepts and Terminology)

- **आर्बिट्रेज (Arbitrage) :** विभिन्न विदेशी मुद्राओं को एक साथ इस उद्देश्य से खरीदना और बेचना जिससे विश्व के विभिन्न बाज़ारों में विदेशी विनिमय दरों में पाए जाने वाले अंतर से लाभ उठाया जा सके, आर्बिट्रेज कहलाता है।
- **एन्युटी (Annuity) :** किसी एक पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक या अधिक किस्तों में होने वाला भुगतान एन्युटी कहलाता है, जैसे- सरकारी ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान।
- **एडवांस डिक्लाइन (Advance decline) :** यह शेयर बाज़ार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने वाला एक माप है। किसी समयावधि में मूल्य वृद्धि को प्रदर्शित करने वाले शेयरों की संख्या का मूल्य ह्रास वाले शेयरों की संख्या के साथ अनुपात ही एडवांस डिक्लाइन कहलाता है।
- **एयर पॉकेट (Air pocket) :** यदि किसी कंपनी के शेयरों के पहले दिन के बंद भाव तथा दूसरे दिन के खुलने वाले भाव में काफी अंतर होता है तो वह स्थिति एयर पॉकेट की होती है। यह कई कारणों से घटित होता है। जैसे कि यदि किसी कंपनी के विषय में कोई प्रतिकूल सूचना आती है तो कंपनी के शेयरों के भाव गिर जाते हैं। शेयरों के भाव में उतार-चढ़ाव की स्थिति का होना सामान्य बात है।
- **अग्रिम कर (Advance tax) :** अग्रिम कर प्रत्येक वर्ष मार्च, सितंबर एवं दिसंबर में देय होता है ताकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही आगामी वित्तीय वर्ष के बजट के संबंध में अपनी राजस्व प्राप्तियों से अवगत हो सके। अग्रिम कर अर्जित आय के आधार पर देय सिद्धांत पर आधारित है।
- **बिटकॉइन (Bitcoin) :** यह समान समूह और जान-पहचान वाले लोगों के बीच इलेक्ट्रॉनिक मनी और पेमेंट नेटवर्क का खुला माध्यम है।
- **आधार प्रभाव (Base effect) :** वर्तमान आँकड़ों की गणना पर पहले के आँकड़ों का पड़ने वाला प्रभाव 'आधार प्रभाव' कहलाता है। स्फीति दर में वृद्धि के संदर्भ में वर्तमान स्फीति दर की गणना पर विगत वर्षों की कीमतों का पड़ने वाला प्रभाव आधार प्रभाव कहलाता है।
- **बूम (Boom) :** अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं की तेज़ी से विस्तार की स्थिति को बूम कहा जाता है। यह स्थिति मंदी के विपरीत है। मांग में वृद्धि के कारण ही किसी उद्योग विशेष में बूम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- **काला बाज़ार (Black market) :** बाज़ार में जमाखोरी द्वारा वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा करके उनकी कीमतों को बढ़ाकर लाभ कमाने को काला बाज़ार कहते हैं।
- **काला धन (Black money) :** जिस धन का हिसाब-किताब अधिकारियों से छिपाकर रखा जाता है, उसे काला धन कहते हैं।
- **बुरा ऋण (Bad debt) :** वह ऋण जिसकी वसूली संभव न हो अथवा संदिग्ध हो, बुरा ऋण माना जाता है।
- **ब्रिज लोन (Bridge loan) :** कंपनियाँ प्राय: शेयर तथा डिबेंचर जारी करके पूंजी का विस्तार करती हैं। कंपनी को शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में तीन माह या उससे भी अधिक समय लगता है। इस समयावधि में अपना कार्य जारी रखने के लिये कंपनियाँ बैंकों से आंतरिक अवधि के लिये ऋण प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार के ऋण को ब्रिज लोन कहते हैं।
- **ब्लू चिप (Blue chip) :** जिन कंपनियों का प्रबंध अत्यधिक कुशल तथा सुदृढ़ है, उन कंपनियों के शेयरों के लिये ब्लू चिप शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनको बेचने तथा खरीदने में कोई कठिनाई नहीं होती।
- **ब्लू बॉक्स (Blue box) :** कृषि समझौते के अनुसार विभिन्न देश उत्पादन के उद्देश्य से कुछ सीमा तक सब्सिडी की अनुमति देते हैं, जैसे-बिजली, सिंचाई, उर्वरक आदि आगतों में दी जाने वाली सब्सिडी। इस सब्सिडी को ही ब्लू बॉक्स कहते हैं।
- **ब्लू कॉलर जॉब (Blue collar job) :** द्वितीयक क्षेत्र से संबद्ध ऐसे श्रमिकों को जो उत्पादन-प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध होते हैं, उन्हें ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456